Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 28-06-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 28 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	भारत, चीन सीमा मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे
Page 03 **Syllabus : GS 3 : Science & Technology**	भारत ने किशनगंगा, रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर 'पूरक पुरस्कार' को अस्वीकार कर दिया
Page 05 **Syllabus : GS 3 : Internal Security**	अवैध आव्रजन को रोकने के लिए असम, मिजोरम ने नियमों का मसौदा तैयार किया
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Governance**	आराम करने का समय नहीं: भारत ने एसडीजी रैंकिंग में ऊपर चढ़ने में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शासन में पीछे रह गया
Page 08 **Syllabus : GS 3 : Science & Technology**	एआई में बड़ा बदलाव
Page 06 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : International Relations**	चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ भारत की नई चुनौती

Page 01 : GS 2 : International Relations

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर चिंगदाओ में हुई द्विपक्षीय बैठक भारत-चीन संबंधों की विकसित होती रूपरेखा में एक महत्वपूर्ण विकास है। इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु सीमा प्रबंधन और सीमा पार आतंकवाद पर भारत की दृढ़ स्थिति की पुन: पुष्टि करना और 2020 की झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास करना था।

India, China to continue dialogue on border issues

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

All for peace: Defence Minister Rajnath Singh with his Chinese counterpart, Admiral Dong Jun, in Qingdao. PTI

Defence Minister Rajnath Singh firmly conveyed India's stance on cross-border terrorism to his Chinese counterpart, Admiral Dong Jun, during a bilateral meeting held on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers' meeting in Qingdao, China, on Friday.

During in-depth discussions on the need to maintain peace and tranquillity along the India-China border, the two Ministers agreed to continue consultations at various levels to achieve progress on issues related to disengagement, de-escalation, border management and eventual delimitation through existing mechanisms.

Mr. Singh acknowledged the work being undertaken by both sides to bring back normalcy to the bilateral ties. He highlighted the necessity of solving complex issues through a structured road map of permanent engagement and de-escalation. He stressed border management and a permanent solution of border demarcation by rejuvenating the established mechanism on the issue.

The two Ministers discussed de-escalation, disengagement, demarcation, and Special Representatives-level talks. Mr. Singh emphasised the need to create good neighbourly conditions to achieve the best mutual benefits and to cooperate for stability in Asia and the world. He called for bridging the trust deficit created after the 2020 border stand-off, by taking action on ground.

He highlighted the important milestone of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. He also appreciated the resumption of the Kailash Manasarovar yatra after a gap of five years. Mr. Singh briefed his counterpart on the Pahalgam terror attack and India's Operation Sindoor aimed at dismantling the terrorist networks in Pakistan.

Mr. Singh held bilateral meetings with the Defence Ministers Lieutenant-General Victor Khrenin of Belarus, Lieutenant-General Sobrizoda Emomali Abdurakhim of Tajikistan, and Lieutenant-General Dauren Kosanov of Kazakhstan.

EDITORIAL
» PAGE 6

मुख्य बिंदु:

1. भारत की स्थिति की पुन: पुष्टि: भारत ने सीमा पार आतंकवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर अपनी स्पष्ट और अडिग स्थिति को दोहराया। श्री सिंह ने पहलगाम हमले जैसे हालिया आतंकी घटनाओं पर चिंता जताई और विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

2. संरचित संवाद तंत्र: इस वार्ता में सीमा विवादों के समाधान के लिए एक संरचित रोडमैप की आवश्यकता पर जोर दिया गया। द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत, जैसे कि विशेष प्रतिनिधियों के स्तर की बातचीत, के तहत विघटन (disengagement), तनाव में कमी (de-escalation), सीमा प्रबंधन और भविष्य में सीमा निर्धारण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यह जमीनी स्तर पर तनावों को प्रबंधित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक संवाद की निरंतरता को दर्शाता है।

3. रणनीतिक संदेश और विश्वास की कमी: 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद विश्वास की कमी को कम करने के महत्व को सामने रखकर, भारत ने यह संकेत दिया कि उसकी रणनीतिक सहनशीलता स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाली प्रगति और सीमा प्रोटोकॉल के सम्मान पर निर्भर है। यह बैठक उच्च-स्तरीय रक्षा वार्ता का एक दुर्लभ अवसर थी, जो यह दर्शाती है कि भारत बिना अपने मूल हितों से समझौता किए संचार को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है।

4. SCO फ्रेमवर्क में भू-राजनीतिक महत्व: यह बैठक SCO जैसे बहुपक्षीय मंच के अंतर्गत हुई, जहां भारत और चीन दोनों ही प्रमुख सदस्य हैं। इससे इस संवाद को राजनयिक वैधता मिलती है और यह इंगित करता है कि भारत रणनीतिक रूप से अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए, विरोधियों के साथ भी बहुपक्षीय मंचों पर संवाद को प्राथमिकता देता है।

5. व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता: "सद्भावनापूर्ण पड़ोसी संबंधों" और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग पर दिया गया जोर द्विपक्षीय एजेंडे को एक बड़े एशियाई और वैश्विक शांति ढांचे से जोड़ता है। यह भारत की एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति और दक्षिण एवं मध्य एशिया में स्थिरता के वाहक के रूप में भूमिका को दर्शाता है।

6. सांस्कृतिक कूटनीति का पुनरारंभ: पाँच वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ द्विपक्षीय संबंधों में सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण को संकेत देता है, जो रणनीतिक तनावों के बावजूद लोगों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

7. व्यापक राजनयिक जुड़ाव: श्री सिंह की बेलारूस, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें यह दर्शाती हैं कि भारत मध्य एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने और एक बहुध्रुवीय क्षेत्रीय संरचना बनाए रखने की दिशा में अपने रक्षा कूटनीति को विस्तार दे रहा है।

निष्कर्ष:

यह घटनाक्रम चीन के साथ भारत की संतुलित कूटनीतिक नीति को दर्शाता है—जहां संवाद और दृढ़ता का संतुलन कायम रखा गया है। यह सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी कूटनीति और बहुपक्षवाद की भारत की बहुस्तरीय रणनीति को परिलक्षित करता है। यह प्रकरण यह भी दर्शाता है कि भारत स्थापित तंत्रों पर भरोसा करता है और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। भारत की विदेश और रक्षा नीति को समझने के लिए इस परतदार दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है, विशेषकर इंडो-पैसिफिक और महाद्वीपीय एशिया के संदर्भ में।

UPSC Mains Practice Question

Ques : हाल ही में भारत-चीन रक्षा मंत्रियों की वार्ता में 2020 के सीमा गतिरोध के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में चुनौतियों और अवसरों दोनों पर प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में, अपनी क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हुए चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रबंधित करने के लिए भारत के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 Words)**

Page 03: GS 2 : International Relations

भारत द्वारा तथाकथित **Court of Arbitration** (CoA) द्वारा जारी "supplemental award" को स्पष्ट रूप से खारिज करना, **सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT)** की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यह प्रकरण न केवल **भारत-पाकिस्तान के बीच गहराते भू-राजनीतिक तनावों** को सामने लाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे संधियों की वैधता और उपयोगिता पर **राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता** की प्राथमिकता हावी हो रही है।

India rejects 'supplemental award' on Kishenganga, Ratle hydropower projects

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

India said it has never recognised the existence in law of this 'so-called' Court of Arbitration

India on Friday "categorically rejected" the "supplemental award" by the Court of Arbitration on Kishenganga and Ratle hydroelectric projects in Jammu and Kashmir, saying that it "never recognised" the Court of Arbitration, a "serious breach" of the Indus Waters Treaty, which has been put "at abeyance" after the April 22 terror attack in Pahalgam.

"India has never recognised the existence in law of this so-called Court of Arbitration, and India's position has all along been that the constitution of this so-called arbitral body is in itself a serious breach of the Indus Waters Treaty and consequently any proceedings before this forum and any award or decision taken by it are also for that reason illegal and per se void," the External Affairs Ministry said after the World Bank's Court of Arbitration gave a "supplemental award" on the Kishenganga and Ratle projects.

'Unilateral action'

Pakistan had been raising objections about the design of the power projects, and the two sides held multiple rounds of discussions till 2015. In 2016, Pakistan approached the World Bank to establish a Court of Arbitration to resolve these technical disputes. Pakistan took three issues concerning Kishenganga and four concerning Ratle to the Court of Arbitration. India's position from the beginning has been that it was a "unilateral action" by Pakistan to approach the World Bank.

Reflecting that position, the Ministry said on Friday, "Today, the illegal Court of Arbitration, purportedly constituted under the Indus Waters Treaty 1960, albeit in brazen violation of it, has issued what it characterises as a 'supplemental award' on its competence concerning the Kishenganga and Ratle hydroelectric projects in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir."

The Ministry said that after the Pahalgam terror attack, India exercised "its rights as a sovereign nation under international law" and placed the Indus Waters Treaty in abeyance, "until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism". It described the Court of Arbitration's declarations as a "charade at Pakistan's behest".

"Until such time that the Treaty is in abeyance, India is no longer bound to perform any of its obligations under the Treaty. No Court of Arbitration, much less this illegally constituted arbitral body, which has no existence in the eye of law, has the jurisdiction to examine the legality of India's actions in exercise of its rights as a sovereign," the Ministry said.

प्रमुख बिंदु:

1. भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और पंचाट की वैधता को अस्वीकार: भारत ने यह दोहराया कि यह पंचाट न्यायालय **अवैध रूप से गठित** है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि यह न्यायालय भारत द्वारा कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं रहा और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय **न्यायिक रूप से अमान्य और शून्य (void)** है। भारत का यह रुख IWT के अंतर्गत तकनीकी विवादों को **द्विपक्षीय वार्ता या Neutral Expert** के माध्यम से सुलझाने की मूल भावना से प्रेरित है।

2. पाकिस्तान का एकपक्षीय रवैया और संधि का उल्लंघन: भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने 2016 में वर्ल्ड बैंक से पंचाट न्यायालय गठन की मांग कर **IWT की स्थापित प्रक्रिया को दरकिनार** कर दिया। किशनगंगा से जुड़े तीन और रैटल परियोजना

से जुड़े चार बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने **तीसरे पक्ष की मध्यस्थता** की मांग की, जिसे भारत ने संधि के मूल तंत्र के विरुद्ध माना।

3. पहलगाम हमले के बाद संधि को 'निलंबित' करना: 22 अप्रैल 2025 को हुए **पहलगाम आतंकी हमले** के बाद भारत ने पाकिस्तान की **आतंकवाद को समर्थन देने की नीति** का हवाला देते हुए **IWT को निलंबित** कर दिया। यह एक **अभूतपूर्व और निर्णायक कदम** है, जहां भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने **संप्रभु अधिकारों** का प्रयोग करते हुए संधि से अस्थायी रूप से खुद को अलग किया।

4. रणनीतिक संदेश और संप्रभुता की पुनः पुष्टि: भारत ने यह संकेत दिया कि **राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता**, संधि दायित्वों से ऊपर है जब दूसरा पक्ष आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा हो। इस कदम से भारत ने न केवल पाकिस्तान की **कूटनीतिक रणनीति को चुनौती दी**, बल्कि IWT के संचालन के भू-राजनीतिक संदर्भ को भी पुनर्परिभाषित किया।

5. IWT पर दीर्घकालिक प्रभाव: यह घटनाक्रम IWT की भावी स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, जो अब तक कई युद्धों और संकटों के बावजूद जारी रही है। भारत द्वारा संधि को **आतंकवाद से जोड़ना**, संधि की प्रकृति में एक **नई रणनीतिक दिशा** का संकेत है, जहां **संधियां अब व्यापक सुरक्षा संदर्भों से अलग नहीं रखी जा सकतीं।**

निष्कर्ष:

भारत द्वारा किशनगंगा और रैटल परियोजनाओं पर "पूरक निर्णय" को खारिज करना केवल एक विधिक विवाद नहीं, बल्कि **गहरे अविश्वास और रणनीतिक टकराव का प्रतिबिंब** है। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संधियाँ भी **राजनैतिक-भू-सुरक्षा संकटों** से अछूती नहीं रहतीं। यह घटनाक्रम भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** को बल देता है और यह स्पष्ट करता है कि भारत अपनी विदेश नीति को अब **राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल तत्वों** के अनुरूप ढाल रहा है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए पूरक निर्णय को भारत द्वारा अस्वीकार करना राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के प्रति उसके दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। सिंधु जल संधि के तहत हाल के घटनाक्रमों के आलोक में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 words)**

Page : 05 : GS 3 : Internal Security

असम और मिज़ोरम द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम — जिनका उद्देश्य पहचान दस्तावेज़ों पर नियंत्रण और सीमा पार अवैध प्रवास पर रोक है — यह दर्शाते हैं कि भारत अब पूर्वोत्तर जैसे **संवेदनशील क्षेत्रों** में **आंतरिक सुरक्षा**, **जनसांख्यिकी प्रबंधन** और **डिजिटल गवर्नेंस** को एक नई रणनीतिक दृष्टि से देख रहा है।

Assam, Mizoram draft rules to curb illegal immigration

Soon, only District Commissioners will have the power to issue Aadhaar cards, says Assam CM; in Mizoram, plans on to confiscate identity cards of Myanmar nationals who frequently cross border

The Hindu Bureau
GUWAHATI

Two northeastern States have toughened their stand on identification documents to curb unauthorised cross-border movements of Bangladesh and Myanmar nationals.

The Assam government has decided to implement a policy to issue Aadhaar cards to adult citizens only through the District Commissioners (DCs) to prevent Bangladeshi nationals from acquiring them, while the Mizoram government plans to retain the identity cards of Myanmar nationals to regulate movement across the border.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said the need to toughen the rules of issuing Aadhaar cards was discussed at the State Cabinet meeting on Friday. "Usually, people who come to Assam and Bharat from Bangladesh [illegally] are adults. Since we have already achieved 100% Aadhaar coverage, we will thoroughly enquire into the applications of new adults," he told press-persons in Guwahati.

High vigilance: BSF personnel patrol the India-Bangladesh border at Golakganj in Dhubri district of Assam. AFP

"Soon, only the DCs will have the power to issue Aadhaar cards. If such a policy is made, it will be difficult for Bangladeshi people to obtain Aadhaar. Detecting and pushing them back will be easy if they do not possess this document," he said, hours after announcing that 20 more illegal Bangladeshi immigrants were pushed back.

The Bharatiya Janata Party-led government has been working on plugging the vulnerabilities of Aadhaar since April, when, Mr. Sarma said, people who did not apply for inclusion in the National Register of Citizens have been barred from getting the unique identification number.

In September 2024, he said that four Assam districts had more Aadhaar cardholders than their projected population. Bengali-speaking Muslims are a majority in these districts – Barpeta bordering Bangladesh, Dhubri, Morigaon, and Nagaon.

"We found that 103.74% of the population were issued Aadhaar cards in Barpeta, 103.48% in Dhubri, 101.74% in Morigaon, and 100.68% in Nagaon. Some immigrants definitely managed to take Aadhaar," the Chief Minister had said.

In Aizawl, Mizoram Chief Minister Lalduhoma proposed the confiscation of the identity cards of Myanmar nationals who cross over into India frequently, amid the civil war in their country. He came up with this proposal at a meeting with Surinder Bhagat, Joint Secretary in the Ministry of External Affairs and Protector General of Emigrants, at the Chief Minister's Office recently.

Acknowledging the humanitarian crisis in Myanmar forcing many to take refuge in Mizoram, Mr. Lalduhoma said, "Many refugees are law-abiding, but there are some who continue to cross the border to and from Myanmar, exploiting the ongoing crisis there."

He warned of stern action against those misusing the shelter provided, including the seizure of their Myanmar-issued identity documents. He suggested that such IDs be collected from each Myanmar national for the duration of their stay in Mizoram.

प्रमुख मुद्दे और विकास:

1. असम में आधार कार्ड नियंत्रण:

मुख्यमंत्री **हिमंत बिस्वा सरमा** ने घोषणा की है कि अब **सिर्फ जिला आयुक्त (DC)** ही नए वयस्कों को आधार जारी कर सकेंगे।

- इसका उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा **जाली पहचान के जरिए आधार कार्ड प्राप्त करने** की संभावनाओं को रोकना है।
- कुछ जिलों (जैसे बरपेटा और धुबरी) में **103% से अधिक आधार कवरेज** पाया गया — जो जनसंख्या से अधिक है, और संभावित **अवैध आव्रजन** की ओर इशारा करता है।
- यह नीति **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)** से भी जुड़ी है — जो आधार को उन्हीं को प्रदान करने की अनुमति देता है जो NRC में शामिल हैं।

2. मिज़ोरम में म्यांमार शरणार्थियों की निगरानी:
मुख्यमंत्री **लालदुहोमा** ने म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के **पहचान पत्र अस्थायी रूप से जब्त** करने का प्रस्ताव दिया है।

- इसका उद्देश्य बार-बार सीमा पार करने वालों पर नियंत्रण रखना और **आतंरिक सुरक्षा** को सुनिश्चित करना है।
- यह **मानवता और सुरक्षा के बीच संतुलन** बनाने का प्रयास है।

3. सीमा सुरक्षा और जनसांख्यिकी चिंता:

- असम की **बांग्लादेश के साथ लगी सीमा** लंबे समय से अवैध आव्रजन का मार्ग रही है।
- मिज़ोरम की सीमा म्यांमार से सटी है, और वहाँ के **चिन समुदायों से सांस्कृतिक और जातीय संबंध** होने के कारण **प्रवर्तन जटिल** होता है।

4. डेटा अखंडता और संस्थागत उत्तरदायित्व:

- आधार और NRC को जोड़ने के प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार **डिजिटल प्रणाली का उपयोग जनसांख्यिकी सत्यापन** के लिए कर रही है।
- यह सुनिश्चित करना कि **कल्याणकारी योजनाओं और पहचान दस्तावेज़ों का लाभ केवल पात्र नागरिकों** को ही मिले — राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम कदम है।

व्यापक प्रभाव:

- **संघीय बनाम मानवीय दायित्व:** मिज़ोरम की कार्रवाई इस पर सवाल उठाती है कि भारत **UN Refugee Convention** से बाहर रहते हुए शरणार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करता है, विशेषकर जब जातीय और मानवीय पक्ष भी जुड़े हों।
- **आधार की वैधता और शासन प्रणाली:** असम की पहल **UIDAI प्रणाली की सीमाओं** को उजागर करती है, और **जैविक पहचान एवं विधिक ढांचे** को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन:** ये उपाय दिखाते हैं कि भारत अब पहचान और नागरिकता जैसे मुद्दों को केवल **प्रशासनिक दस्तावेज़ी प्रक्रिया** नहीं, बल्कि एक **रणनीतिक उपकरण** के रूप में देख रहा है — विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में।

निष्कर्ष:

पूर्वोत्तर भारत में उठाए जा रहे ये कदम यह संकेत देते हैं कि भारत की नीति अब **सुरक्षा, डेटा-आधारित प्रशासन, और जनसांख्यिकी नियंत्रण** के परस्पर संगम पर केंद्रित है। नागरिकता और पहचान अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि **राजनयिक और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति** का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं।

UPSC Mains Practice Question

Ques: असम और मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्यों को अवैध अप्रवास के कारण अद्वितीय जनसांख्यिकीय और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चर्चा करें कि कैसे आधार जैसी पहचान प्रणाली और स्थानीय शासन ढाँचे का उपयोग मानवीय चिंताओं को संतुलित करते हुए ऐसे सीमा-पार आंदोलनों को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। **(250 Words)**

Page 06 : GS 2 : Governance

संयुक्त राष्ट्र के Sustainable Development Solutions Network (SDSN) द्वारा प्रकाशित Sustainable Development Report (SDR) 2025 में भारत का शीर्ष 100 देशों में प्रवेश (99वाँ स्थान) एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2016 में 110वें स्थान से यह प्रगति नीतिगत प्रयासों की सफलता को दर्शाती है, विशेषकर गरीबी उन्मूलन, बिजली पहुँच, और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में। हालांकि, यह प्रगति सत्ता, पोषण, और शासन से संबंधित कुछ गहरे मुद्दों को छिपा भी लेती है, जो दीर्घकालिक सतत एवं समावेशी विकास के लिए चुनौती हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति:

1. गरीबी उन्मूलन (SDG 1):

- 2012 में लगभग 22% गरीबी दर से 2023 में लगभग 12% तक गिरावट (World Bank के अनुसार)।
- लेकिन 2018 के बाद खपत व्यय डेटा उपलब्ध नहीं, और गरीबी रेखा (जैसे रंगराजन रेखा) पुरानी हो चुकी है।
- इससे नीति नियोजन और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता में **डेटा पारदर्शिता की आवश्यकता** उजागर होती है।

2. बिजली उपलब्धता (SDG 7):

- भारत ने लगभग सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है।
- सौर और पवन ऊर्जा में निवेश के चलते भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता तैनातकर्ता बन चुका है।
- लेकिन गुणवत्ता, स्थायित्व और क्षेत्रीय असमानता अब भी एक चुनौती हैं।

3. अवसंरचना और डिजिटल समावेशन (SDG 9):

- मोबाइल और UPI आधारित वित्तीय समावेशन में बढ़ोत्तरी हुई है।
- फिर भी, ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर विशेष रूप से COVID-19 के दौरान उजागर हुआ — जिससे शिक्षा (SDG 4) और सार्वजनिक सेवाओं तक समतुल्य पहुंच प्रभावित हुई।

लगातार बनी चुनौतियाँ:

1. भूख और पोषण (SDG 2):

- क्रॉनिक कुपोषण अभी भी एक गंभीर समस्या है:
  - स्टंटिंग: 35.5% बच्चे प्रभावित (NFHS-5)

No time to rest

India did well in climbing up SDG rankings, but falls short in governance

India has been ranked among the top 100 countries in the Sustainable Development Report for the first time since this data began to be published by the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) since 2016. The SDSN is an independent body under the aegis of the UN, whose publications are tracked by policymakers and governments. In 2016, India was ranked 110th out of 157 countries, making steady progress to reach 99 this year out of an expanded basket of 167 nations with better metrics and more granular comparisons. But it is no time to rest on this laurel. India must look at why this incline, by 11 points, was not achieved any sooner and the gaps to focus on. From a developmental perspective, the SDSN ranks India as having fared better in poverty reduction (SDG 1) even as India's poverty estimation continues to be mired in controversy due to a lack of publicly available consumption expenditure data since 2018 and the poverty line (Rangarajan line ~₹33/day rural, ₹47/day urban) not having been updated. Proxy data suggest a considerable poverty reduction, almost halving between 2012 (22% based on NSSO data) and 2023 (World Bank - 12%).

But SDG 2 (zero hunger) has remained a cause for concern. It also reveals the wide disparity between income groups and rural and urban areas on access to a nutritious diet. The National Family Health Survey (NFHS) estimates that over a third of Indians (35.5%) were stunted (NFHS-5, 2019-21), only marginally better than 38.4% (NFHS-4, 2015-16). Similarly, wasting, which is low weight for height, reduced from 21.0% to 19.3%. Obesity in the working age population (15-49 years) has almost doubled between 2006 and 2021, and concentrated in wealthier urban areas. Electricity access (SDG 7) is another indicator where India has done well. While the country has achieved near universal household electrification in the past two decades, the quality of power and duration vary vastly based on regions and urban/rural fault lines. It is, however, laudable that India today ranks as the fourth largest renewables capacity deployer, mainly solar and wind. And while India has bettered its score in infrastructure provision (SDG 9), noteworthy additions being rapid mobile penetration and financial inclusion through UPI-linked digital payments gateways, COVID-19 revealed the stark difference between rural and urban Internet penetration, which must be addressed to achieve even higher educational outcomes (SDG 4). It is telling, however, that throughout the Modi years, India's performance in governance, the rule of law, press freedom and strong and independent institutions (SDG 16) has been lagging.

- वेस्टिंग: 19.3%
- मोटापा: 15–49 आयु वर्ग में लगभग दोगुना (मुख्यतः शहरी और धनी वर्ग में)

- भारत को अब तीनहरे पोषण संकट — अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, और अधिक पोषण (over-nutrition) — का सामना करना पड़ रहा है।

2. शासन और संस्थागत प्रदर्शन (SDG 16):

- भारत अब भी कानून का शासन, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक क्षमता, और संस्थागत स्वतंत्रता के मामले में पिछड़ रहा है।
- इससे लोक विश्वास में गिरावट, और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व में कमी आती है।
- कमजोर संस्थान दीर्घकालिक विकास को बाधित कर सकते हैं।

नीति और योजना पर प्रभाव:

- SDG में भारत की प्रगति आत्मसंतोष नहीं, बल्कि कमजोर क्षेत्रों में सुधार हेतु प्रेरणा बननी चाहिए, विशेषकर पोषण और सुशासन।
- मजबूत संस्थान, पारदर्शी डेटा प्रणाली, और समावेशी सेवा वितरण आवश्यक हैं।
- पूरे शासन तंत्र और समाज को सम्मिलित कर SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत की SDR रैंकिंग में सुधार निश्चित रूप से सराहनीय है, परंतु यह नीतिगत सजगता और वास्तविक सुधार की भी मांग करता है। पारदर्शिता, संस्थागत मजबूती, और पोषण में सुधार के बिना यह प्रगति अस्थायी सिद्ध हो सकती है। 2030 के SDG एजेंडा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, भारत को डेटा-आधारित, समावेशी और न्यायपूर्ण विकास मॉडल को अपनाना होगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में भारत की बढ़त बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन में मापनीय सफलता को दर्शाती है, लेकिन शासन और पोषण में संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर करती है। डेटा, विकेंद्रीकृत शासन और समावेशी विकास की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसडीजी को प्राप्त करने में भारत की प्रगति की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 Words)**

Page : 08 : GS 3 : Science & Technology

भारत के आईटी, स्वास्थ्य, वित्त, निर्माण, और सेवा क्षेत्र में तेज़ी से फैलती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कार्यबल की प्रकृति को गहराई से बदल रही है। बेंगलुरु, भारत का एआई केंद्र, इस बदलाव का प्रमुख उदाहरण है। 1 लाख से अधिक AI पेशेवरों के साथ भारत अब बड़े पैमाने पर श्रम बाज़ार के पुनर्गठन की दहलीज़ पर खड़ा है।

The big AI shake-up

While Bengaluru is home to more than a lakh artificial intelligence professionals, AI has also brought with it fears of job loss. The launch of a survey recently by Karnataka's Department of Information Technology and Biotechnology to assess the impact of AI on the workforce is an indication of the State getting set to face up to this multi-dimensional issue, writes **Shilpa Elizabeth**

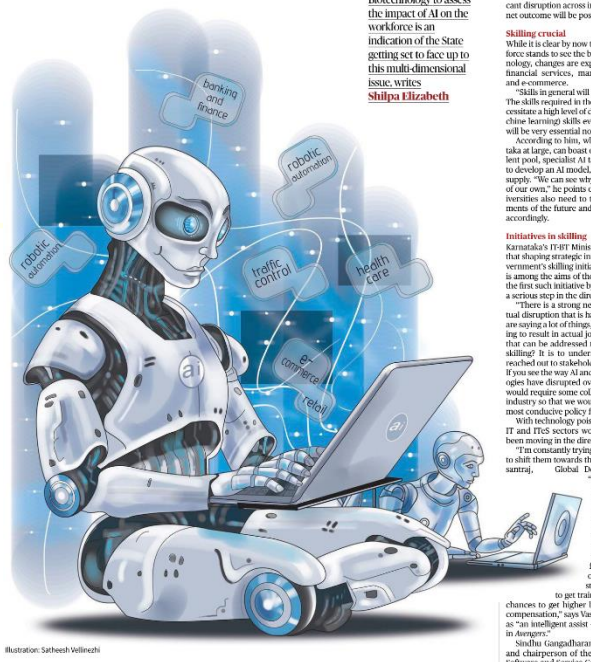

Illustration: Satheesh Vellinezhi

At a leading hospital in Bengaluru, an artificial intelligence (AI)-enabled invoice digitisation system was implemented around four months ago.

"Initially, the invoice details were documented on paper, and later entered manually into the system. Now, the job is being done by AI, which extracts details from the soft copies of invoices," says Vijay (name changed), who is overseeing the project and a few other AI initiatives at the hospital.

According to him, automation brought down human intervention in the process by at least 50%. "No one has been laid off. People were only repurposed," he says while admitting that the development may affect recruitments in the future.

Hima (name changed), a consultant at one of the biggest accounting firms, was part of an office meeting recently where people were encouraged to share their apprehensions on the firm's AI implementations. "Some of our coders were very upbeat about the introduction of AI. There is a resource crunch in the coding team, and they are often very stretched. But with the firm investing in AI tools and code assistants, they say life has become easier for them," she notes.

Multifaceted effects

As AI reshapes the workforce across sectors, its effects are proving to be multifaceted, and far from uniform.

Bengaluru is today home to more than a lakh AI professionals. The city was also recently ranked among the top five AI ecosystems in the Global Startup Ecosystem Index. With Bengaluru positioning itself in the thick of AI advancements and the Karnataka government now on the cusp of launching the next IT policy, the State's Information Technology and Biotechnology Department recently launched a survey to assess the impact of AI on the workforce.

> Skills in general will undergo massive change. Those required in the new world of AI will necessitate a high level of digital literacy. AI-ML skills even in non-technical roles will be very essential now.
>
> **GURUPRASAD MUDLAPUR,** vice-chairman of CII Karnataka and vice-president of Bosch Group in India

Among other things, it aims to understand how AI is being integrated into day-to-day operations across organisations, which business functions are seeing the biggest changes, and which job roles are most vulnerable to automation.

The survey is an indication of the State taking serious note of the big shake-up that is on our doorstep.

The AI-augmented future

From enhancing precision in surgeries to detecting fraud in banking and finance, enabling robotic automation in manufacturing, powering personalised recommendations in retail, and optimising traffic control in cities, AI is becoming increasingly ubiquitous and almost indispensable. According to the United Nations, the global AI market is projected to reach $4.8 trillion by 2033.

The other side of this, however, is the fears of lay-off and displacement, especially in jobs involving routine and repetitive tasks, coupled with a growing sense of overwhelm as workers struggle to adapt to an ever-evolving workplace. A recent report by the United Nations Conference on Trade and Development predicted that AI would impact 40% of the jobs worldwide and widen inequality. Amazon CEO Andy Jassy's recent comment about the company moving to a smaller corporate workforce due to the adoption of generative AI tools and agents has not helped allay fears, particularly as the tech giant has laid off more than 27,000 employees since 2022.

What is going to be the net result of this disruption and how is it going to play out in India?

"I think, in the future, all of us will be AI-augmented humans," says Guruprasad Mudlapur, vice-chairman of the Confederation of Indian Industry, Karnataka, vice-president of Bosch Group in India, and managing director of Bosch Ltd. While acknowledging the possibility of significant disruption across industries, he believes the net outcome will be positive.

Skilling crucial

While it is clear by now that the IT and ITeS workforce stands to see the biggest impact of the technology, changes are expected in sectors such as financial services, manufacturing, healthcare, and e-commerce.

"Skills in general will undergo massive change. The skills required in the new world of AI will necessitate a high level of digital literacy. AI-ML (machine learning) skills even in non-technical roles will be very essential now," remarks Mudlapur.

According to him, while Bengaluru, or Karnataka at large, can boast of the highest AI-ready talent pool, specialist AI talent – which is required to develop an AI model, for example – is in short supply. "We can see why we have not built a GPT of our own," he points out, while adding that universities also need to take note of the requirements of the future and act on training students accordingly.

Initiatives in skilling

Karnataka's IT-BT Minister Priyank Kharge notes that shaping strategic interventions under the government's skilling initiative, NIPUNA Karnataka, is among the aims of the AI survey. The survey is the first such initiative by a State government and a serious step in the direction of skilling.

"There is a strong need to understand the actual disruption that is happening. A lot of people are saying a lot of things, but is that disruption going to result in actual job loss, or is it something that can be addressed through reskilling or upskilling? It is to understand this that we have reached out to stakeholders through the survey... If you see the way AI and other emerging technologies have disrupted over the last four years, we would require some collective feedback from the industry so that we would be able to give out the most conducive policy for growth," he says.

With technology poised to change the way the IT and ITeS sectors work, companies too have been moving in the direction of skilling.

"I'm constantly trying to repurpose my people to shift them towards the demand," says Ravi Vasantraj, Global Delivery Head, Mphasis. "I'm now changing my talent management systems to start allowing for people to get trained or hyper-personalised in their training. Let's say someone is a full-stack Java developer, but we are seeing demand for people with React.js or Node.js skills. We will start prodding this person to get trained in them, showing his chances to get higher billing and hence higher compensation," says Vasantraj who likes to see AI as "an intelligent assist – like J.A.R.V.I.S. to Stark in *Avengers*."

Sindhu Gangadharan, MD of SAP Labs India and chairperson of the National Association of Software and Service Companies, notes that the company offers curated learning journeys tailored to individual skill profiles, leveraging internal platforms, global partners, and partnerships with institutions such as IIM Bangalore, IIIT Bangalore, BITS Pilani, and Northwestern Kellogg. "The result is a future-ready workforce empowered to lead with an AI-first mindset. Today, 50% of our employees are already AI-enabled. Over the past year alone, they've completed more than 35,000 courses and clocked over 2,00,000 learning hours," she says.

Multiplying demand?

With almost every corporate investing in AI and demand for AI agents and tools increasing, the number of AI roles has also risen, creating a large demand for people trained in the same. A recent report by Naukri JobSpeak recorded a 25% year-on-year rise in hiring for AI and ML roles in India.

"It (AI) will create more than it will alter," says Vasantraj, who believes that not only will the technology not take away jobs, but will probably multiply the demand 10 times and enhance the productivity of employees.

"The combined industry of North America, Europe, and Asia-Pacific spends anywhere between $1.8 trillion and $1.9 trillion to support legacy technology. This is known as tech debt. People are worried that they will lose their jobs to AI. But our premise is that these $1.9 trillion will come into the market because now it's viable."

According to him, the latent demand from clients who were earlier reluctant to deploy AI is now getting activated. Mphasis witnessed its pipeline jumping up by an unprecedented 70% between quarters three and four in the last financial year, he notes.

In contrast: Balaji Parthasarathy, professor at IIIT Bangalore and principal investigator of the Fairwork India project, argues that in India, the impact of AI on the workforce will pan out differently as compared with the West. GETTY IMAGES

The other half

The high demand for AI talent in IT and ITeS is, however, only half the story, say sources within the industry. While there is demand, the elephant in the room is the immense pressure on AI development teams within companies, says Radhika (name changed), who works as a project manager at the Bengaluru office of a global technology and service supplier.

"Companies like ours have purchased AI technologies from behemoths like Google or OpenAI for huge prices. The investment has been massive, and they need returns. To get the desired results, they put immense pressure on AI development teams, often pushing them to the brim," she notes. According to her, most IT and ITeS companies have so far not been able to achieve the expected efficiency or profits by deploying AI in place of people. "Coding assistance is the only use case that is working to some extent," she says.

> Our industry evolves very quickly. This industry was written down after Y2K. But we are shape-shifters, and we keep learning. My view is that there will be a decoupling between revenues and headcount, which means that with the same number of people, you'll be able to multiply revenues.
>
> **RAVI VASANTRAJ,** Global Delivery Head, Mphasis

The way forward then, has been to extract more out of the remaining employees, alleges Radhika.

"Even when they haven't fixed the issues with the existing AI tools, they invest in more. This will not only burden the employees, but also reduce the quality of products and services in the industry going forward," she says, citing the example of the customer services function, where several companies witnessed lower customer satisfaction after trying to replace executives with AI bots.

Technology vs. labour

Balaji Parthasarathy, professor at IIIT Bangalore and principal investigator of the Fairwork India project, argues that in India, the impact of AI on the workforce will pan out differently as compared with the West. He points out how some companies, for example, have abstained from deploying AI in certain roles in India, simply because the labour is cheap and pliant, and labour laws are loosely enforced.

"If you look at the warehouses of big companies like Amazon in the U.S., there are high levels of automation. In many parts of the world, they are experimenting with drones for delivery. But in a country like India, where labour is relatively inexpensive, it doesn't make as much sense. It may, in fact, be costlier for companies to bring in these technologies. Here, workers are replaced easily because there is high levels of unemployment and labour rights are not strictly enforced."

Sector-specific debate

He notes that the AI vs. jobs debate is also sector-specific and a function of whether the AI tools can deliver on the organisational priorities. "In areas where you require precision or the job is hazardous, deployment of AI or robotics is critical. If there are tasks that can be easily automated at very low costs, AI will be used for them. Then there are fields where the technology will enter but will require human beings to know how to use them to augment what they do, rather than displace them. I think the word 'augment' is not considered enough," says Parthasarathy.

The fear of job loss is not entirely baseless though, admits Mudlapur. Repetitive manual skills may be the most vulnerable, and these might involve job roles such as coding, invoice processing, accounting, and research assistance. Mid-skilled white-collar jobs like analyst might also get replaced if they do not have deep domain knowledge, he remarks.

"We see the coding efficiency going up by 30% if we adopt AI, GPTs, and other tools to enhance the codes. But we can also say we may not require 30% of the software talent. But a positive way to look at it is this 30% could do more sophisticated work, like building models and so on," he says. "Overall, there will be a shake-up in the job market. That is very clear."

The shape-shifters

Vasantraj of Mphasis feels the anxieties, at least concerning the job losses in the IT/ITeS sector, are part of the usual fears before any new technology takes off. "Our industry evolves very quickly. This industry was written down after Y2K. But we are shape-shifters, and we keep learning. My view is that there will be a decoupling between revenues and headcount, which means that with the same number of people, you'll be able to multiply revenues," he notes, attributing the lay-offs at the companies to macroeconomic factors rather than AI.

According to Vasantraj, regulations, responsible AI, and data breaches should be the bigger concerns.

"If AI is combined with quantum, you have a real problem. Your Gmail could be hacked in 30 seconds. Given the kind of geopolitical situations, there will be characters that might start using it in an obtuse manner. It's similar to nuclear energy in that sense. If you have a J.A.R.V.I.S. with Stark, you will also have a Thanos somewhere. But that's a problem for tomorrow," he says.

AI से उत्पन्न प्रमुख आयाम:

1. स्वचालन बनाम रोज़गार की चिंता:

- AI ने इनवॉइस प्रोसेसिंग, लेखांकन, और बेसिक कोडिंग जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर दिया है।

- इससे मध्यम-कौशल वाले पदों में नौकरी छूटने की आशंका बढ़ी है।
- हालांकि, कंपनियाँ जैसे Mphasis और SAP इसे "बुद्धिमान सहायक" के रूप में देखती हैं, जहां कर्मचारियों को हटाया नहीं गया, बल्कि पुन: कौशल-प्रशिक्षण दिया गया।

2. संवर्द्धन बनाम प्रतिस्थापन:

- भारत में AI की भूमिका मुख्यतः मानव क्षमताओं को बढ़ाने (augment) वाली बनी रह सकती है, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में।
- भारत में सस्ती श्रम लागत और कमजोर श्रम सुरक्षा के कारण, कई कंपनियाँ स्वचालन को टालती हैं।

3. क्षेत्र-विशेष प्रभाव:

- IT/ITeS: कोडिंग की दक्षता में 30% की वृद्धि, लेकिन कर्मचारी संख्या में कटौती की चिंता भी।
- स्वास्थ्य: निदान, रोबोटिक सर्जरी और अस्पताल प्रबंधन में सुधार।
- वित्त/खुदरा: धोखाधड़ी पहचान, व्यक्तिगत सिफारिशें, और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण में उपयोग।
- ग्राहक सेवा: बॉट्स के प्रयोग से संतुष्टि स्तर घटा, जो भावनात्मक कार्यों में AI की सीमाएँ दर्शाता है।

सरकार और उद्योग की प्रतिक्रियाएँ:

1. कर्नाटक सरकार की सक्रिय पहल:

- IT-BT विभाग ने भारत में पहली बार एक AI प्रभाव सर्वेक्षण शुरू किया है।
- इसका उद्देश्य है कि NIPUNA कौशल कार्यक्रम के तहत रणनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित हो और भविष्य के लिए एक नीति-संगत कार्यबल तैयार किया जा सके।

2. उद्योग-प्रेरित कौशल पहलकदमियाँ:

- Mphasis आंतरिक प्रतिभा गतिशीलता और हाइपर-पर्सनलाइज़्ड प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहा है।
- SAP Labs India ने 2 लाख से अधिक लर्निंग घंटे पूरे किए हैं; इसके 50% कर्मचारी पहले से ही AI-सक्षम हैं।
- यहां तक कि गैर-तकनीकी भूमिकाओं में भी अब AI-ML दक्षता और डिजिटल साक्षरता आवश्यक हो गई है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- AI विशेषज्ञों की कमी: भारत के पास पर्याप्त AI-प्रशिक्षित जनबल है, लेकिन कोर AI डेवलपर्स और शोधकर्ताओं की भारी कमी है।
- कर्मचारी थकान और लाभ अपेक्षा: कंपनियाँ त्वरित परिणामों की उम्मीद में आंतरिक टीमों पर अत्यधिक दबाव डाल रही हैं।
- असमानता में वृद्धि: उच्च-कौशल वाले कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, जबकि निम्न-कौशल और असंगठित कार्यबल जोखिम में है।

- नैतिकता और साइबर सुरक्षा: AI + क्वांटम कंप्यूटिंग का मेल भविष्य में गंभीर साइबर खतरे उत्पन्न कर सकता है।

भारत के लिए व्यापक निहितार्थ:

- AI रोज़गार के मानकों, उत्पादकता और क्षेत्रीय संरचना को फिर से परिभाषित करेगा।
- इसके लिए आवश्यक हैं:
    - कौशल, शिक्षा और श्रम सुधारों में रूपांतरणात्मक बदलाव
    - मजबूत डेटा सुरक्षा कानून
    - समावेशी अनुकूलन नीतियाँ, विशेषकर युवाओं और ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए

UPSC Mains Practice Question

Ques: "एआई न केवल नौकरियों की जगह लेगा, बल्कि उन्हें नया आकार भी देगा।" हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, चर्चा करें कि भारत एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में कार्यबल की तत्परता कैसे सुनिश्चित कर सकता है। **(250 words)**

Page : 06 Editorial Analysis

A China-led trilateral nexus as India's new challenge

Harsh V. Pant

is Vice-President, Observer Research Foundation

Aditya Gowdara Shivamurthy

is Associate Fellow, Neighbourhood Studies, Observer Research Foundation

Last week, China, Pakistan and Bangladesh held their first trilateral meeting in Kunming, China. The discussions focused on furthering cooperation and exploring the possibilities of deeper engagement. This meeting closely follows another trilateral meeting between China, Pakistan, and Afghanistan, held in May, with the aim of extending the China-Pakistan Economic Corridor and increasing cooperation. These trilaterals, led by China, come at a time of Pakistan's little relevance to the region, India's increasing relations with Afghanistan, and New Delhi's deteriorating ties with Bangladesh. The use of trilaterals underscores China's fresh attempts at making Pakistan a stakeholder in the region and keeping New Delhi preoccupied with immediate concerns.

A war that shaped alignments

The 1962 war between India and China has largely shaped regional alignments and geopolitics. Following the war, China found Pakistan to be an ally that could keep India engaged with immediate threats and limit it from challenging Beijing's interests, security, and status. On the other hand, Pakistan deemed China to be a country that would unquestionably offer economic and military assistance to support its aggression against India. To date, Pakistan is highly dependent on China for assistance, investments and infrastructure development. In fact, by the end of 2024, Pakistan had a loan of over $29 billion from China. It is estimated that over 80% of Pakistan's arms imports are from China. In addition, China has also shielded Pakistan-backed terrorists at the United Nations Security Council and other multilateral platforms.

This camaraderie was largely visible during India's Operation Sindoor in May 2025. China termed India's retaliation to the Pakistan-sponsored attack in Pahalgam as "regrettable" and urged a political solution and dialogue. It backed Pakistan's stance of initiating an investigation into the Pahalgam terror attack in April 2025. The latest escalation also saw Pakistan deploying various Chinese-made hardware and weapons that ranged from surveillance radars, drones, missiles, guidance systems, and fighter jets. In the immediate aftermath of Operation Sindoor, Pakistan's Foreign Minister met his Chinese counterpart to reaffirm its "iron-clad friendship." The trilateral with Afghanistan and other countries likely emerged from this meeting.

The Beijing-led trilaterals are aimed at challenging India's long-term interests

The resurfacing of an idea

This idea of China and Pakistan using plus one against India is not a new phenomenon. Even in 1965, Pakistan flirted with the idea of using East Pakistan, China and Nepal to cut off India from its strategic Siliguri corridor. This idea of using South Asian countries seems to have resurfaced as both China and Pakistan face a confident India. Pakistan-sponsored terror attacks in Uri (2016), Pulwama (2019), and Pahalgam have seen India retaliate in a befitting manner. It has shown that India will no longer tolerate Pakistan's nuclear blackmail. India has also used its diplomatic clout and growing economy to isolate Pakistan. India's suspension of the Indus Waters Treaty, halting trade, restricting port access, and targeting military installations – all as a part of its retaliatory measures against the Pahalgam attack – has damaged Pakistan military's operational capacities and confidence, highlighting Rawalpindi's limitations and weaknesses. India's military and diplomatic responses to Chinese border intrusions in Doklam and Galwan have also likely taken Beijing by surprise. New Delhi has also increased close cooperation with like-minded countries to limit Chinese aggressions.

At the same time, India's pragmatic engagement and domestic politics of the region have slowed down China's momentum in South Asia. In the Maldives, Beijing appears reluctant to trust President Mohamed Muizzu and the country's economy, despite his initial anti-India rhetoric. Mr. Muizzu has now turned to India to keep the country's economy afloat. In Nepal, despite signing the framework for Belt and Road Initiative (BRI) cooperation, major differences in funding remain unresolved and the progress of projects has been slow. In Sri Lanka, President Anura Kumara Dissanayake is developing close ties with India by respecting its redlines. Despite ideological and historical differences with Delhi, he visited India before China. In the case of Bangladesh, despite differences, India has not hindered the trilateral energy cooperation with Nepal.

These increasing anxieties are likely to have motivated China to push for trilaterals with Afghanistan and Bangladesh. Before their respective regime changes in 2021 and 2024, both countries were staunch supporters of India's fight against both Pakistan and its state-sponsored terrorism. With the change in regimes, however, Pakistan and China have attempted to draw both countries closer to their orbit. They remain cautious of pragmatic engagement between India and the Taliban, fearing that Pakistan would lose its leverage. At the same time, Pakistan has increased security, economic and political engagements with the new government in Bangladesh.

Historically, both Bangladesh and Afghanistan have enjoyed close ties with Pakistan and provide a fertile ground for cross-border terrorism. Pakistan's influence, supported by China and its economic clout, could thus create new terror and security-related challenges. This will help Pakistan become a relevant country in the region, create rifts between India and its neighbours, and keep Delhi preoccupied with immediate security and terror-related challenges, making way for Chinese BRI projects, interests and investments in the region.

China efforts and setbacks

The developments in the region demonstrate, once again, that China, and not Pakistan, is India's biggest challenge. With both Pakistan and China confronting a confident India, China sees an opportunity to challenge India through the trilateral nexus. At a time when India is seeking support from South Asian countries to fight terrorism, Chinese efforts will create new setbacks. South Asian countries will thus have to learn to balance between India and China, as Beijing uses Islamabad to create new complexities in the region. On its part, Delhi will have to continue to express redlines and convey the point that any misadventures by its neighbours could have severe economic, military, and political costs.

Paper 02 International Relations

UPSC Mains Practice Question : पाकिस्तान और भारत के पड़ोसियों को शामिल करते हुए चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय समूहों का उदय भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती पेश करता है। भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तरह के गठबंधनों के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 words)

Context :

चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश त्रिपक्षीय बैठक (कुनमिंग) और इसके पूर्व चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय संवाद ने दक्षिण एशिया में चीन द्वारा संचालित एक नवीन क्षेत्रीय कूटनीति की शुरुआत का संकेत दिया है। यह रणनीति शीत युद्ध की घेराबंदी नीति की याद दिलाती है, जिसका उद्देश्य भारत को राजनयिक रूप से अलग-थलग करना, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमज़ोर करना, और Belt and Road Initiative (BRI) के माध्यम से चीन की भूराजनीतिक जड़ों को मजबूत करना है।

प्रमुख रणनीतिक निष्कर्ष:

1. त्रिपक्षवाद के माध्यम से चीन की क्षेत्रीय पुनर्संरचना:

- यह त्रिपक्षीय प्रयास पारंपरिक द्विपक्षीय रणनीति से हटकर क्षेत्रीय समूहों के निर्माण की ओर बढ़ता संकेत हैं, जो चीन-केंद्रित हितों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
- बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों को सम्मिलित कर, चीन भारत की वैश्विक स्थिति को संतुलित करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार कर रहा है।

2. पाकिस्तान की भूमिका: रणनीतिक विघ्नकारी (spoiler):

- आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर पाकिस्तान चीन पर निर्भर है — $29 अरब डॉलर से अधिक ऋण और 80% सैन्य आयात चीन से।
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी सैन्य उपकरणों का उपयोग और आतंकवाद से जुड़े विमर्शों में चीन-पाक की सामरिक सामंजस्यता उजागर होती है।

3. भारत की प्रतिकारात्मक रणनीति:

- भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमले, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सशस्त्र जवाबों और संधियों (जैसे सिंधु जल संधि) और व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से राजनयिक दबाव बनाया है।
- भारत की तालिबान शासन के साथ संवाद, तथा श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी इसका प्रमाण हैं कि भारत अब व्यावहारिक कूटनीति को अपना रहा है।

उभरती सुरक्षा चिंताएँ:

- बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों की नीतिगत दिशा में बदलाव, उन्हें चीन-पाक धुरी की ओर झुका सकता है, जिससे सीमा पार आतंकवाद और खुफिया खतरे फिर उभर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को चीन द्वारा सुरक्षा देना इस खतरे को और बढ़ाता है।
- इससे भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति, आर्थिक कूटनीति, और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।

चीन के रणनीतिक उद्देश्य:

- पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में प्रवेशद्वार बनाना, ताकि भारत सीमा विवाद और आतंकी गतिविधियों में उलझा रहे।
- राजनैतिक रूप से लचीले पड़ोसी देशों में BRI परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
- भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव को चुनौती देकर सॉफ्ट पावर को कमज़ोर करना।

भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया:

- भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आपसी सम्मान और आर्थिक साझेदारी के आधार पर द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा है।
- भले ही मतभेद हों, भारत ने ऊर्जा व संपर्क परियोजनाओं को नहीं रोका, जो विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है।
- मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों को अब यह अहसास हो रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक और सामरिक जोखिम ला सकती है।

निष्कर्ष:

चीन-पाक त्रिपक्षीय गठजोड़ को भारत को केवल राजनयिक गठबंधन के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। चीन जहां क्षेत्रीय विभाजनों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत को अपनी नीति में रणनीतिक दृढ़ता, सक्रिय कूटनीति और स्पष्ट 'लाल रेखाएँ' (redlines) बनाए रखनी होंगी। आतंकवाद, आर्थिक दबाव, और कूटनीतिक चालबाज़ी से उत्पन्न खतरे भारत की दक्षिण एशिया नीति में पुनर्संरेखण की मांग करते हैं, जिसमें सख़्ती और रचनात्मक संवाद का संतुलन हो।